लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2419

21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र हेतु पीएलआई योजना

2419. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना पर खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितनी कंपनियां लाभान्वित हुई हैं;

(ख) वस्त्र क्षेत्र के कुल निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान वस्त्र क्षेत्र में कितनी नौकरियों का सृजन किया गया है;

(ग) उद्योग की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की कपास के लिए एमएसपी रखने और किसानों की आय बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) पीएलआई योजना से राज्य को वस्त्र क्षेत्र में किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(च) पीएलआई योजना के तहत सहायता के लिए चयनित कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): सरकार ने देश में वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने के लिए एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ दिनांक 08.09.2021 को उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को स्वीकृति दी है। वस्त्र के लिए पीएलआई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 जेस्टेशन अवधि है। निष्पादन वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होकर 2028-29 तक होगा। योजना के तहत संवितरण वर्ष 2025 से शुरू होगा।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

(अमरीकी बिलियन डॉलर)

वस्तु	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात	37.55	38.40	35.18	31.59	44.44

स्रोतः डीजीसीआईएस के अनंतिम आंकड़े, आंकड़े राउंड ऑफ किए गए हैं

कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जा रहा है।

(ग): सरकार, देश में विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र), समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना), सिल्क समग्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना आदि विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है । इसके अलावा, सरकार वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में संपन्न समझौता; और विभिन्न व्यापारिक भागीदारों के साथ 6 तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) शामिल हैं। वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट को जारी रखा। इसके अलावा, अन्य वस्त्र उत्पाद जो आरओएससीटीएल के तहत शामिल नहीं किए गए हैं, वे अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत आते हैं।

सरकार व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वस्त्र और अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(घ): सरकार राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए और अन्य प्रासंगिक कारकों, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर कपास (मध्यम स्टेपल) और कपास (लंबी स्टेपल) की दो किस्मों सहित 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी के साथ वृद्धि की है। इसी सिद्धांत के अनुरूप, सरकार ने सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है।

वर्ष 2022-23 (01.10.2022-30.09.2023) सीजन के लिए कपास की एमएसपी 6080 रुपये प्रति क्विंटल (मीडियम स्टेपल) और 6380 रुपये प्रति क्विंटल (लॉन्ग स्टेपल) निर्धारित की गई है, जो पिछले कपास सीजन वर्ष 2021-22 की कीमत से लगभग 6% अधिक है।

(ङ) और (च): वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना में 64 भागीदार हैं। इस योजना से 19,798 करोड़ रुपये का निवेश होने और 2.45 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वस्त्र के लिए पीएलआई योजना अखिल भारतीय आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। चयनित कंपनियां न्यूनतम निवेश और न्यूनतम/वृद्धिक कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पाने की पात्र होंगी।

*****